चौथा संसार, इन्दौर 21 OCT 2010

नई उद्योग नीति में बड़े निवेश की संभावना बढ़ी, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

५० व ९० फीसदी स्थानीय लोगों को रोज़गार पर रियायत से उद्योग व क्षेत्र दोनों का फायदा

औद्योगिक रूप से पिछड़े मध्यप्रदेश को अब गति देने के कुछ खास प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए शासन ने उद्योगों पर जो शर्तें लागू की है, वह व्यापक हित में है। उद्योग यदि ५० फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देते हैं तो रियायतें और बढ़े उद्योग ९० फीसदी नौकरी देते है तो और बड़ी रियायत। सरकार एक नवम्बर से नई उद्योग नीति लागू करने जा रही है। नई उद्योग नीति २००४ उद्योग नीति का स्थान लेगी। उधर, प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने एकेडमी और साइंस फार टू डवलपिंग वर्ड की वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि उद्योग विकसित देशों के विकास पटर्न पर अंध अनुसरण नहीं करें। यह संयोग ही था कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन यह बात कही उसी दिन मध्यप्रदेश शासन की नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में यह बात कही जो मायने रखती है। मध्यप्रदेश औद्योगिक मीट वर्ष २०१० का खजुराहों में २२ व २३ तारीक को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के देश के बड़े उद्योगपति और विदेशी उद्यमी आएंगे। मध्यप्रदेश उद्योग नीति को कुछ प्रधानमंत्री की सहाल भी मानना चाहिए। उद्योगों को बढ़ाना देने के लिए फिलहाल जो नीति अपनाई जा रही है वह पश्चिमात्य औद्योगिकी करण की नकल है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उद्योगों की स्थापना ही देश में रोजगार देने के साथ पर्यावरण में सुधार करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने उद्योग नीति पर यह नया दृष्टिकोण जाहिर किया है जिसको अमल में लाने से देश का एक नया परिदृश्य बनेगा। आज पर्यावरण व रोजगार की समस्याओं का निदान मध्यप्रदेश शासन ने अपनी नई उद्योग नीति में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की जो शर्त रखी वह अच्छी तो है, लेकिन उसका परिचालन कितना होता है यह देखना होगा। शासन को यह भी देखना चाहिए कि उपजाऊ जमीन उद्योगों की स्थापना से बची रहे। आजकल उद्योगों के नाम पर किसानों से जमीन छुड़ाने का धंधा ज़ोरों पर चल रहा है। शासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योगों की जरूरत से मुताबिक जमीन आवंटित की जाए। कुल मिलाकर नई उद्योग नीति प्रदेश में नए रोजगार को विकसित करेगा।